

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ३६६ राँची, शुक्रवार

1 ज्येष्ठ, 1937 (श॰)

22 मई, 2015 (ई॰)

जल संसाधन विभाग

संकल्प

6 मई, 2015

विषय:- प्रथम झारखंड जल संसाधन आयोग का गठन ।

संख्या-2/पी0एम0सी0/विविध/68/2003 (भाग-1) -322-- जल झारखंड राज्य के गठन के पूर्व बिहार द्वारा अक्टूबर, 1967 में प्रथम बिहार राज्य सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं में मूलतः राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की वास्तविक गणना किया जाना था तािक इनका उपयोग सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल, जल विद्युत उत्पादन, औद्योगिक उपयोग, इत्यादि हेतु किया जा सके। पुनः बिहार सरकार द्वारा दिनांक 06 मार्च, 1991 को द्वितीय बिहार राज्य सिंचाई आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अगस्त, 1994 में बिहार सरकार को अपनी अनुशंसा सींपी।

2. बिहार राज्य के पुनर्गठन एवं ग्लोबल वार्मीन्ग के कारण जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप नवसृजित झारखंड राज्य के समेकित विकास हेतु राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित नदी बेसिनों में जल की अद्गतन उपलब्धता, विकास तथा प्राकृतिक संतुलन के साथ इसके बहु आयामी उपयोग एवं कुशल प्रबंधन

के लिये विस्तृत कार्यनीति तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गयी। जलवायु परिवर्तन पर जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार केये गये राष्ट्रीय जल मिशन के प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु तैयार की गयी कार्यनीतियों को मूर्त रूप देने हेतु झारखंड में प्रथम झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत झारखंड में निम्नरूपेण प्रथम झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है।

3. आयोग का संगठनात्मक स्वरूप निम्नवत् होगा :

(i)	मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखंड, रांची	अध्यक्ष
(ii)	जल संसाधन विकास विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता के स्तर का)	पूर्णकालीन सद्स्य
(iii)	जल प्रबंधन विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता के स्तर का)	पूर्णकालीन सद्स्य
(iv)	मृदा संरंक्षण विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता के स्तर का)	पूर्णकालीन सद्स्य
(v)	अर्थशास्त्री / विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता के स्तर का)	पूर्णकालीन सद्स्य
(vi)	कृषि विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता के स्तर का)	पूर्णकालीन सद्स्य
(vii)	औधोगिक विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता के स्तर का)	पूर्णकालीन सद्स्य
(viii)	बाढ़ प्रबंधन विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता के स्तर का)	पूर्णकालीन सद्स्य
(ix)	समाज विज्ञान विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता के स्तर का)	पूर्णकालीन सद्स्य
(x)	सदस्य (जल आयोजन) केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार	अंशकालिन सदस्य
(xi)	प्रधान सचिव/ सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड, रांची	अंशकालिन सदस्य
(xii)	प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, रांची	अंशकालिन सदस्य
(xiii)	प्रधान सचिव/ सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड, रांची	अंशकालिन सदस्य
(xiv)	प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, रांची	अंशकालिन सदस्य

(xv) प्रधान सचिव/ सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखंड, रांची

- अंशकालिन सदस्य
- (xvi) प्रधान सचिव/ सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड, रांची
- अंशकालिन सदस्य
- (xvii) जल संसाधन क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त अंशकालिन सदस्य विशेषज्ञ
- (xviii) उपकुलपति, बिरसा कृषि विश्वविधालय, झारखंड, रांची

अंशकालिन सदस्य

(xix) निदेशक, बीO आईO टीO, मेसरा, रांची

अंशकालिन सदस्य

- (xx) कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करनेवाले जल संसाधन क्षेत्र में अंशकालिन सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त एन० जी० ओ० के एक प्रतिनिधि (मनोनयन बाद में किया जाएगा)
- (xxi) समाजसेवी संस्थानों का प्रतिनिधित्व करनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय एवं अंशकालिन सदस्य राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त एन० जी० ओ० के एक प्रतिनिधि (मनोनयन बाद में किया जाएगा)
- (xxii) जल, कृषि, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में विशेष आमंत्रित विशेषज्ञता रखनेवाले सांसद / विधान सभा सदस्य एवं अन्य सदस्य विशेषज्ञ (अधिकतम चार सदस्य जिनका मनोनयन बाद में किया जाएगा)
- 4. इस आयोग का कार्यालय तीन वर्षों के लिये होगा। यह अविध अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा।
- 5. आयोग पर तीन वर्षों में आवर्तक तथा अनावर्तक कुल रू० 572.64 लाख का व्यय संभावित है।
- 6. प्रथम झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के लिये कार्यकलाप (Term of Reference) एवं संपादित किये जानेवाले कार्यों के लिए समय सारिणी निम्नरूपेण निर्धारित की गई है।

क्रमांक	कार्यकलाप का विवरण	कार्यकलाप का अध्ययन हेतु	प्रस्तावित बैठ्कों की
		संभावित समय	संख्या
1.	राष्ट्रीय जल नीति में दिए गये प्रावधानों के आलोक में राज्य में जल संसाधन का विकास एवं प्रबंधन की वर्तमान नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना। राज्य के सूखा एवं बाढ़ की समस्याओं, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, क्षेत्रीय विषमताओं आदि के संदर्भ में सिंचाई, पेयजल, उद्योग एवं जल विद्युत उत्पादन, औधोगिक एवं अन्य कार्यों, में जल के उपयोग को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सुधार एवं सुझाव देना।	1 माह	2
2.	पूर्ववर्ती सिंचाई आयोगों द्वारा प्रत्येक बेसिन/उपबेसिन में जल की गुणवता के साथ उनका अध्ययन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करना। चालू एवं निर्माणाधीन योजनाओं के माध्यम से जल संसाधनों के उपयोग के वर्तमान स्तर को निर्धारित करना एवं उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए प्रावैधिकी विकल्पों के बारे में सलाह देना तथा भविष्य में मौसम में होने वाले बदलाव के मद्देनजर जल की मांग, भूमि-उपयोग, वर्षा, वाष्पीकरण में होने वाले परिवर्तन को आकलित करना।	1 माह	2
3.	झारखण्ड राज्य के निर्माण के उपरांत सह बेसिन राज्यों के साथ राज्य सरकार द्वारा किए गये सभी अंतर्राज्यीय एकरारनामों के प्रावधानों की समीक्षा करना एवं जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन से सम्बन्धित राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के समग्र ढ़ाँचे के अंतर्गत राज्य के हितों की रक्षा एवं भविष्य के लिए नीति निर्धारण के बारे में परामर्श देना।	1 माह	2
4.	प्रमुख नदी बेसिनों के लिए जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन की सर्वांगीण योजना की रूप-रेखा तैयार करना।	2 माह	4
5.	वर्तमान संगठनात्मक, वैधिक एवं कार्यपालक प्रावधान के अंतर्गत, सम्पोषण, प्रचालन तथा जल प्रबंधन के साथ-साथ अंतर्विभागीय समन्वय जैसे मुद्दों की जाँच करना तथा इन्हें मजबूत एवं सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक अनुशंसायें करना ताकि जल संसाधन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण/ सुरक्षा की नई चुनौतियों का	2 माह	4

	सामना किया जा सके।		
6.	पूरी की गई नदी बेसिन परियोजनाओं के कार्योत्तर प्रतिवेदनों का अध्ययन करना एवं राज्य में वर्तमान परियोजनाओं की कार्यक्षमता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपायों की अनुशंसा करना।	2 माह	4
7.	विभिन्न अधिनियमों, नियमों, अध्यादेशों एवं कार्यपालक आदेशों, भारत सरकार के विधि आयोग द्वारा मॉडल सिंचाई संहिता की जाँच कर राज्य की कृषि एवं सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप एक मॉडल सिंचाई संहिता का प्रारूप तैयार करना, ताकि सिंचाई जल प्रबंधन, जलकरों के मूल्यांकन एवं वसूली तथा अभिलेखों का उचित रख-रखाव हो सके।	2 माह	4
8.	विस्तृत अध्ययन कर बेसिन या अंतर्बेसिन में जल की कमी वाले क्षेत्र से नालों/नदियों को जोड़कर जलांतरण करने की विभिन्न संभावनाओं का पता लगाना।	2 माह	4
9.	वर्षा जल के रिजिम एवं प्रबंधन के तरीकों में बदलाव के कारण मृदा क्षरण को रिभर बेसिन में रोकने के उपाय खासकर वैसी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र में जो राज्य के विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित है।	2 माह	4
10.	बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण विकास सिहत जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन से सम्बन्धित किसी अन्य मामले का परीक्षण एवं उपर्युक्त उपायों का सुझाव देना और कोई भी अन्य मामला, जिसे राज्य सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किया जाए।	1 माह	2
11.	योजनाओं के रख-रखाव को स्व वित्त पोषित बनाने के लिए सिस्टम मैनेजमेंट की व्यवस्था लागू करने हेतु प्रतिवेदन तैयार करना।	2 माह	4
12.	राज्य को अधिक प्रभावकारी लाभ उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई, औद्योगीकरण एवं अन्य राज्यों/संस्थानों को जल उपलब्धता के आधार पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष राजस्व ढांचा का अध्ययन कर प्रतिवेदन देना।	2 माह	4
13.	संपूर्ण राज्य के जलीय सूचना प्रणाली के विकास हेतु स्वचालित मौसम केन्द्र का व्यापक तंत्र स्वचालित वर्षामापक केन्द्र, स्वचालित	3 माह	6

	\$117 G 3 1010 (01711417 1) 1331417, 22 014, 1		
	सेंसर के माध्यम से आँकड़ा संग्रहण नेटवर्क के साथ वाष्पीकरण मापक यंत्र, सभी निदयों एवं उनकी सहायक निदयों पर जलश्राव, सेडीमेंट एवं जल की गुणवत्ता की जाँच हेतु स्थल, नदी ज्यामिति एवं मॉर्फोलॉजी पर नेटवर्क की स्थापना कर आँकड़ों का संग्रहण, संकलन, विश्लेषण एवं इन आंकड़ों को वेवपोर्टल पर उपलब्ध कराना तािक इन आंकड़ों को उपयोग करने वाली एजेंसी द्वारा प्राप्त किया जा सके। इस सूचना प्रणाली में जल ग्रहण क्षेत्र की मैपिंग, भूमि के उपयोग करने के तरीके जिनमें जल निस्सरण, हरितछाजन, वनछाजन, भूमि-अतिक्रमण तथा हूयमन सेटलमेंटस भी दर्शित करना।		
14.	कृषि योग्य भूमि में फसल के बीच तथा सिंचित क्षेत्रों में फसल के जड़ो के बीच उपलब्ध नमीय मृदा से होने वाली वाष्पीकरण को कम करना तथा रिर्टन वाटर को चिन्हित कर इसके पुर्न उपयोग को बढ़ावा देते हुए जल उपयोग करने की क्षमता को 20% प्रतिशत तक बढाने के संबंध में जल के अधिकतम उपयोग के लिए एक कार्य प्रणाली को विकसित करना।	2 माह	4
15.	विषम परिस्थिति में उपलब्ध जल का उपयोग करने वाली विभिन्न प्रजातियों की फसलों को चिंहित एवं मूल्यांकित करना, अनुक्ल क्रोपिंग पैर्टन की डिजाइनिंग करना, समेकित फार्मिंग सिस्टेम को अपनाना तथा जल के प्रभावकारी उपयोग करने के संबंध में इंसेंटिभ प्रणाली को विकसित करना।	3 माह	6
16.	खनिज की निकासी के उपरांत बेकार पड़े उत्खनित खानों में अतिरेक बाढ़ जल के बहाव को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव की पहचान करना तथा भू-गर्भ जल की पंपिग कर भू-गर्भ जल स्तर को बाढ़ आने के पहले नीचे किया जाना ताकि पंपिग के माध्यम से भू-गर्भ जल में बनाये गये खाली जगह को बाढ़ के जल से पुनर्भरित कर कंजंक्टिव यूज आफ वाटर को समयानुसार सुनिश्चित करना।	2 माह	4

17.	पर्यावरण पर पूर्ण, चालू एवं प्रस्तावित जल संसाधन परियोजनाओं के कारण पड़ने वाले संभावित प्रभाव की पहचान, परीक्षण, आकलन तथा मूल्यांकण करना एवं पर्यावरण पर पड़ने वाली प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए रिमेडियल एक्शन प्लान की कार्य योजना तैयार करना।	2 माह	4
18.	जल संसाधन परियोजनाओं को पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरिशप के तहत कार्यान्वित करने हेतु चिन्हित करना तािक सिंचाई क्षमता के दर में बढोत्तरी की जा सके। साथ ही अव्यवहृत सतिही जल का दोहन कर कृषि एवं औद्योगिक जल की बढती हुई मांग को पूरा करते हुए राज्य के सकल घरेलु उत्पाद को कृषि एवं औधोगिक क्षेत्र में होने वाली सम्भावित वृद्धि के माध्यम से सहयोग किया जा सके।	2 माह	4
19.	भू-गर्भ जल एक्यूफर (पोटैंशिल फ्रैक्चर जोन) तथा वर्षा जल संचयन के माध्यम से कृत्रिम रूप से पुर्नभारित करने हेतु उपयुक्त स्थलो को चयनित किया जाना ताकि इनका दोहन सिंचाई समेत विभिन्न उपयोगों के लिए किया जा सके।	2 माह	4

- 7. प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग के संचालन के लिये जल संसाधन विभाग में कार्यरत नियमित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रुप में आयोग कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जायगा।
- 8. प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग में अनुभवी अभियंताओं, अर्थशास्त्री, कृषि विज्ञान संकाय के प्रतिनिधियों, राजनीतिज्ञ तथा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित तीन विभिन्न स्तरों पर चिन्हित किये गये ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को विशेषज्ञ सदस्यों के रुप में शामिल किया जायेगा। आयोग में इन विशेषज्ञ सदस्यों में से कुछ की सेवा-अविध पूर्णकालिक एवं कुछ सदस्यों की अंशकालिक होगी। आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों के रुप में सरकारी/गैर सरकारी संगठन से सेवा निवृत ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को विशेषज्ञ सदस्यों के रुप में संविदा पर रखा जाएगा।

- 9. आयोग के सदस्यों को मानदेय, डी०ए०, टी० ए० एवं अन्य भतों के भुगतान के लिए, वित विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र/संकल्प में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10. आयोग पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उपशीर्ष-14-झारखण्ड सिंचाई आयोग का गठन, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय मद में भारित होगा। इस राशि की निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान, प्रमण्डल सं0-2, राँची होंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(ह0/-) अस्पष्ट, प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग ।
